लोकतंत्र पर प्रहार

नागरिक अधिकारों का हनन

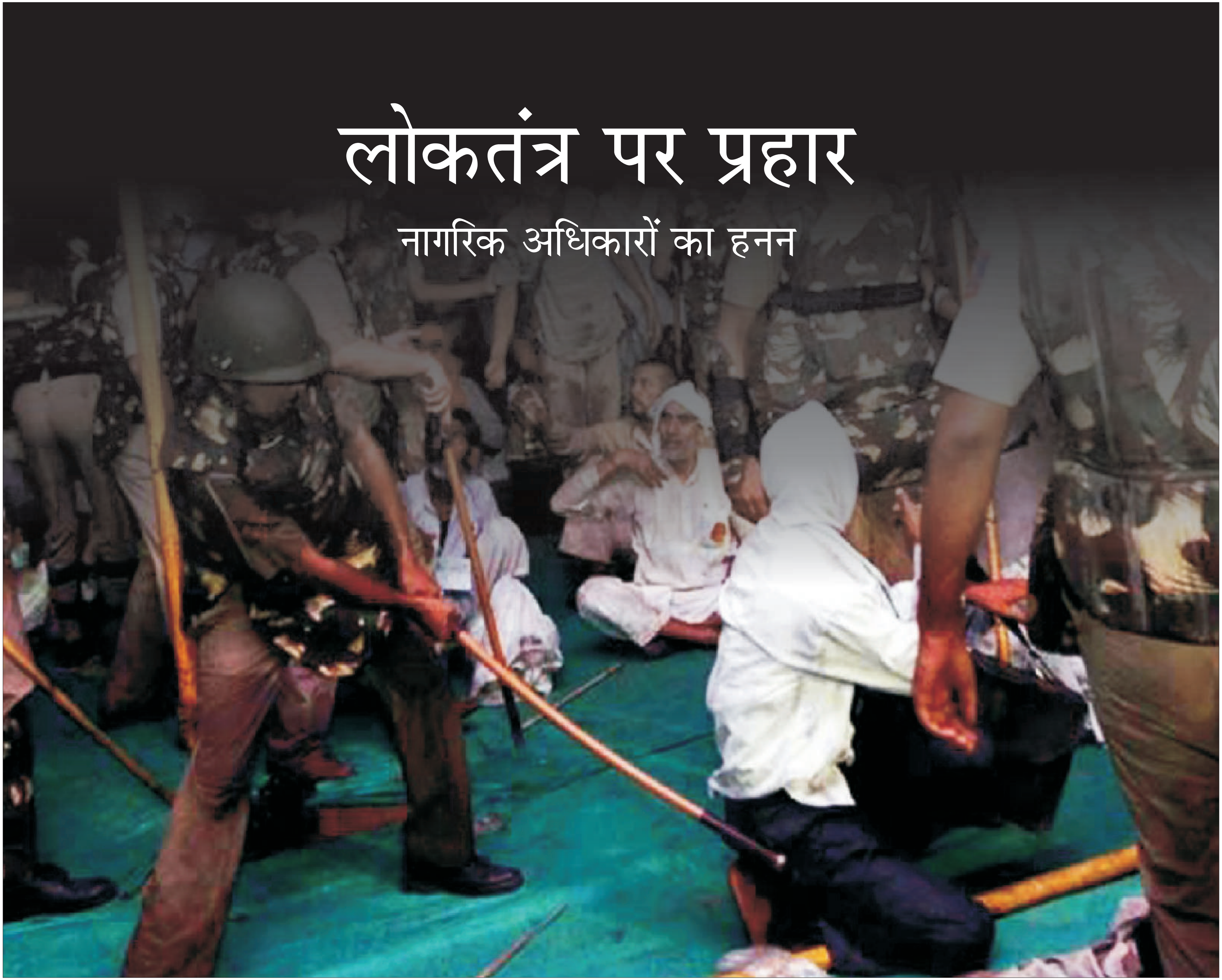

लोकतंत्र पर प्रहार

नागरिक अधिकारों का हनन

भारत नीति प्रतिष्ठान
हौज खास, नई दिल्ली–110016

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी और ढंग से, प्रकाशक की पूर्व अनुमति के द्वारा नहीं किया जा सकता।

प्रकाशक

भारत नीति प्रतिष्ठान

डी-51, हौज खास

नयी दिल्ली-110016 (भारत)

दूरभाष : 011-26524018

फैक्स : 011-46089365

ई-मेल : indiapolicy@gmail.com

संस्करण : प्रथम, 2011

© भारत नीति प्रतिष्ठान

मूल्य : 50 रुपये मात्र

मुद्रक

नागरी प्रिण्टर्स

नवीन शाहदरा, दिल्ली 110032

अधिनायकवादी व्यवस्था बनाम जन एकजुटता

4 जून 2011 की मध्यरात्रि में ऐसी कौन सी विवशता थी जिसने केंद्र सरकार को दिल्ली के रामलीला मैदान में निहत्थे और नींद में सोए सत्याग्रहियों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य कर दिया था?बाबा रामदेव के नेतृत्व में सत्याग्रह का यह पहला दिन था। सत्याग्रह स्थल के बाहर और भीतर कोई उत्तेजना नहीं थी। उल्टे सरकार 2 जून से बाबा रामदेव के साथ 'वार्ता' कर रही थी। 99 प्रतिशत मुद्दों पर 'सहमति' का दावा भी सरकार ही कर रही थी। इसलिए 4 जून की मध्यरात्रि की घटना व्यवस्था की संवेदनहीनता, अमर्यादा, अनाचार के साथ–साथ विश्वासघात का भी एक उदाहरण बन गया है।

सच्चाई यह है कि सरकार सत्याग्रह से सहमी हुई थी। महंगाई, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अनाचार के साये में जी रहे भारतवासियों का धैर्य किस कदर टूट चुका है वह अन्ना हजारे को मिले अपार जनसमर्थन से दिखाई पड रहा था। जिस देश में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग जूझ रहे हों वहां विरोध का स्वर नहीं उठे यह कैसे हो सकता है?भारत के सिर्फ आठ राज्यों में 26 अफ्रीकी देशों की तुलना में अधिक गरीब लोग हैं। एक तरफ भारत के इन राज्यों में यह संख्या 420 लाख है तो 26 अफ्रीकी देशों में 410 लाख गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं तो दूसरी तरफ देश मे असमानता का नया ग्राफ भी तैयार हो रहा है।

तभी तो कालेधन का चौंकानेवाले आंकड़ों पर जन प्रतिक्रिया एवं सामाजिक–सांस्कृतिक संगठनों की आंदोलनात्मक सक्रियता ने शासक वर्ग एवं सत्तारूढ़ पार्टी दोनों को भयभीत कर रखा है। अतः वे इस मुद्दे से देश एवं समाज का ध्यान बंटाना चाहते हैं। इस क्रम में सरकार देश में सांप्रदायिक एवं जातीय ध्रुवीकरण कर व्यवस्था विरोधी जन एकजुटता को समाप्त करने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है। परंतु उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। भ्रष्टाचार एवं कालेधन का मुद्दा लोगों को आंदोलित कर रहा है। सोनिया गांधी निर्देशित सरकार मेकियावेली (इटली के राजनीतिक चिंतक) के अनाचारी सिद्धांतों का अनुकरण कर अपना दामन बचाने में लगी है। 2 जून 2011 को सरकार के चार मंत्री (जिनमें वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री प्रणब मुखर्जी शामिल हैं) अप्रत्याशित ढंग से बाबा रामदेव की अगुआई करने एयपोर्ट पर जाते हैं। उनका उदेश्श्य जन लोकपाल विधेयक की तरह कालेधन के विरोध के स्वर को भी उलझाना था। पर जब इसमें सफलता नहीं मिली तब चरित्र हनन, दुष्प्रचार और दमन के द्वारा आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। बाबा रामदेव को 'महाठग' कहनेवालों को पहले यह बताना चाहिए कि केंद्र सरकार के चार मंत्री किसी 'महाठग' की अगुवानी करने क्यों गए थे?

मुद्दा व्यक्ति नहीं, काला धन है। सरकार एवं राजनीतिक प्रतिष्ठान इसके लिए कितनी तत्परता दिखाता है यह प्रश्न लोगों के सामने है। जन

प्रतिरोध जिस गति से उठ रहा है उसे कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान रोक नहीं सकता है। **प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र (Representative Democracy)** जब सीमाओं में बंधकर काम करता है और जनाकांक्षाओं, जनभावनाओं और जनसमस्याओं के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, लाचारी और आलस्य का प्रदर्शन करता है तो दलीय व्यवस्था के बाहर जन–ध्रुवीकरण होना अति स्वाभाविक है। ऐसा ही 1974 में भी हुआ था। तब आंदोलनकारियों ने अपने जनप्रतिनिधियों को संदेश दिया था कि "तुम नहीं रहे जन प्रतिनिधि हमारे कुर्सी–गद्दी छोड़ दो।" गौरतलब है कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाले व्यवस्था समर्थकों ने तब इसका प्रतिवाद जनतंत्र की ही दुहाई देकर किया था– "लोकसभा/विधानसभा को छोड़ो मत– जनतंत्र को तोड़ो मत'।

इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में दुष्प्रचार, जातीय एवं सांप्रदायिक मुद्दों का सहारा लेकर विपक्ष एवं जन आंदोलनों को कमजोर करने का प्रयास किया था। परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। चेतावनी के तौर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 4 नवंबर 1974 को समानान्तर जनता सरकार बनाने की घोषणा की थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने उनपर संविधान तोड़ने, उत्तेजना फैलाने और कानून–व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया था। अखिल भारतीय विधार्थी परिषद एवं समाजवादी युवजन सभा की सक्रियता सरकार को रास नहीं आई। सरकार ने तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सामने रखकर जे.पी. एवं उनके सहयोगियों पर निशाना साधा था। परंतु जे.पी. ने परिपक्वता के साथ उसकी उपेक्षा की। अधिनायकवाद की प्रतीक बनी इंदिरा गांधी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से पूरे देश में फासीवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया। परंतु सरकार के सभी उपकरण निष्प्रभावी सिद्ध हुए।

लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता को कोई भी व्यवस्था चुनौती नहीं दे सकती है न ही कोई व्यवस्था जन भागीदारी, जन–पहल और जन आंदोलनों को अवैधानिक कह सकती है। राजनीति चुनावी तंत्र का पर्यायवाची नहीं है। यह समाज और राज्य के संचालन की एक प्रक्रिया है। अतः हर जागरूक नागरिक राजनीतिक है। इसके लिए उसे किसी राजनीतिक दल से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसका हस्तक्षेप नैतिक एवं वैधानिक ही नहीं अपेक्षित भी है। जे.पी. आंदोलन इसका उदाहरण है। तब जन हस्तक्षेप ने एक तरफ अधिनायकवाद को परास्त किया था तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक दलों को जनांदोलन के पीछे सहयोगी बनने के लिए प्रेरित एवं बाध्य किया था।

भागीदारीयुक्त लोकतंत्र (Participatory Democracy) **प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र** (Representative Democracy) की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसके आधार को मजबूत करता है, इसे अंकुश में रखकर अराजक होने से रोकता है। यह राजनीति के दायरे को भी बढ़ाता है। नए नेतृत्व एवं कार्यकर्ताओं की नई टोली और राजनीति के नए आयाम को जन्म देता है। 1977 की घटना इसका एक उदाहरण है। सामाजिक–सांस्कृतिक संगठन, निर्दलीय सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन, मीडियाकर्मी, विश्वविद्यालय परिसर ये सभी भागीदारी युक्त लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। आर्थिक उदारीकरण की चुनौतियों एवं राज्य की सिमटती भूमिका ने भागीदारी युक्त लोकतंत्र के प्रभाव को और भी प्रबल बना दिया है। इस बदलाव के संकेत को शासक वर्ग आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता है। वर्तमान सरकार ने Participatory

Democracy को अनैतिक, अवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताकर इसे कुचलने का प्रयास किया है। इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब अधिनायकवादी ताकत जनतांत्रिक शक्ति को परास्त कर पाई हो। कालेधन एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध वर्तमान आंदोलन जन–पहल, बौद्धिकता, विशेषज्ञता, और व्याकुलता चारों का सम्मिश्रण है। भारत में जन आंदोलनों के इतिहास में पहली बार समस्या के साथ–साथ समाधान को सामने रखकर जन–कार्रवाई की जा रही है। दलीय व्यवस्था में व्याप्त न्यूनताओं एवं इसकी सीमाओं के कारण एक बड़ा वर्ग इससे बाहर रहकर जनतांत्रिक पहल कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है?जे.पी. ने भी दलविहीन प्रजातंत्र की बात की थी। संसद या विधानमंडल तक ही जनतंत्र पांच वर्षों तक पिंजराबद्ध होकर तोते की तरह परंपरागत शैली में काम करे, यह जीवंत और गतिवान समाज की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इसे राह दिखाना, जन भावनाओं के अनुकूल करना भागीदारी युक्त लोकतंत्र का कर्तव्य है। वर्तमान व्यवस्था ने उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक–सांस्कृतिक संगठनों को निशाना बनाना शुरु किया है जो भारत के नए लोकतंत्र के सारथी हैं। बाबा रामदेव के नेतृत्व के सत्याग्रह को जिस प्रकार कुचला गया वह भारतीय जनतंत्र के लिए अशुभ संकेत और अधिनायकवादी कार्रवाई का एक प्रयोग है। इस प्रकार के दमनकारी व्यवस्था को एकजुटता से प्रत्युत्तर देना ही लोकतंत्र की रक्षा करना है।

4 जून की मध्यरात्रि की घटना ने लोकतंत्र को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। यह दस्तावेज उसी काली रात का एक बयान है जो आपातकाल की याद को न सिर्फ ताजा करती है औपनिवेशिक काल में जनरल डायर के कुकृत्यों की एक झांकी भी प्रस्तुत करता है। भ्रष्टाचार और कालेधन के साये से देश को निकालने की मुहिम लोकशाही के लिए अवसर और चुनौती दोनों हैं। मीडिया ने जिस प्रखरता के साथ एकजुट होकर इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई की निंदा की है वह अपने आप में भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। भारत नीति प्रतिष्ठान ने काले धन के मुद्दे एवं पुलिस प्रशासन तथा जांच एजेंसियों के दुरूपयोग रोकने के लिए नीतियों का निर्माण हेतु जनजागरूकता हो, इस अपेक्षा से इस दस्तावेज को तैयार किया है। इसमें प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से जिन समाचारपत्रों से सहायता मिली है उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। इस क्रम में श्री विशाल तिवारी, जयराम, अमरेश, नवनीत, शिव एवं ललित का सहयोग भी उल्लेखनीय रहा हैं।

21 जून, 2011

प्रो. राकेश सिन्हा
मानद निदेशक
भारत नीति प्रतिष्ठान

जन–पहल, जनसक्रियता और जन भागीदारी

देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और कालेधन को लेकर आवाम का आक्रोश सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। पुरी व्यवस्था अनाचार और लूट–खसोट में किस कदर लिप्त है यह एक लाख 76 हजार करोड़ के 2जी घोटाला व राष्ट्रमंडल खेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार से जाहिर होता है। इस बीच देश विदेश की एजेंसियों द्वारा जारी भारत में कालेधन का चौंकानेवाले आंकड़ों ने होश उड़ा दिए। जन लोकपाल विधेयक का दस्तावेज जन–पहल, जन–भागीदारी और जन–असंतोष के प्रतीक के रूप में सामने आया।

4 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जन लोकपाल विधेयक के समर्थन में जंतर–मंतर पर अनशन पर बैठे। इसके समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। राजनीतिक शुचिता के लिए स्वतःस्फूर्त उत्साह ने सरकार को चौंकाया। चार दिनों के भीतर ही केंद्र सरकार ने उनकी मांगें 'मान' ली। परंतु यह सब छलावा सिद्ध हुआ। जन आक्रोश को शांत करने की यह एक नरम रणनीति थी। काले धन एवं भ्रष्टाचार का मुद्दा देश को झकझोर रहा है। जिसे बाबा रामदेव ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठित रूप प्रदान करने का काम किया। कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश को व्यक्त करने एवं ठोस नीति निर्माण के लिए वैधानिक, राजनीतिक एवं राजनयिक पहल हेतु बाबा रामदेव के नेतृत्व में दलविहीन आंदोलन का दूसरा दौर 4 जून के सत्यग्रह से शुरू हुआ।

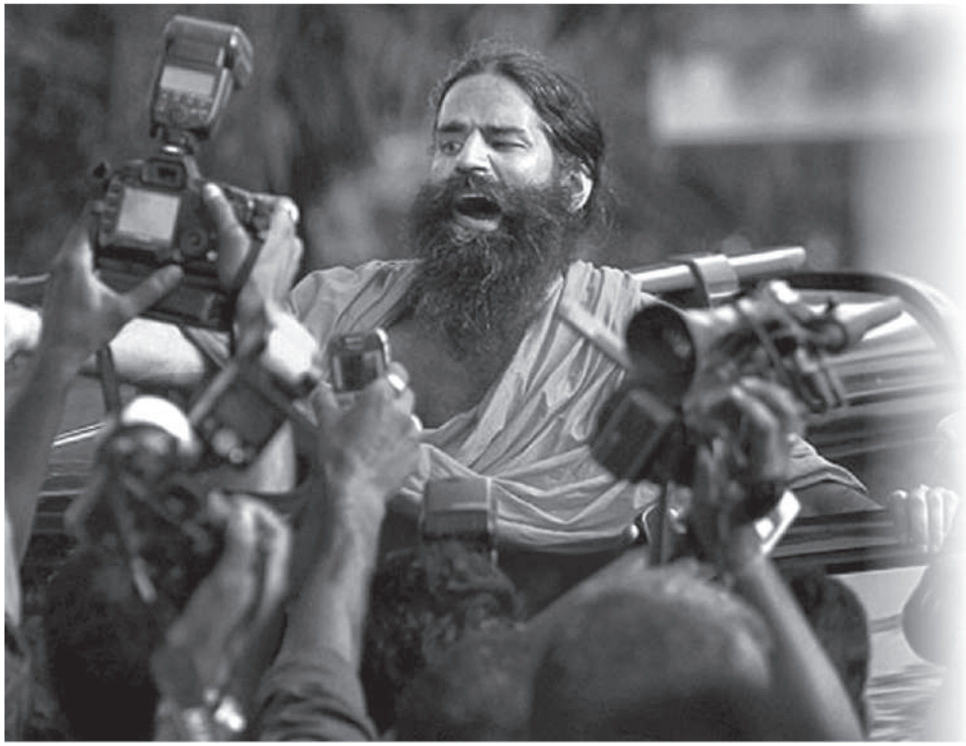

यह अचानक नहीं हुआ। कालेधन को उजागर करने एवं जन चेतना पैदा करने में मीडिया ने सार्थक भूमिका निभाई। 30 जनवरी 2011 को रामलीला मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा में कालेधन को लेकर सरकार से तत्परता दिखाने, पहल करने, जनभावनाओं के अनुकूल कदम उठाने का आग्रह हुआ। पर जो राजनीतिक व्यवस्था खुद भ्रष्टाचार से पोषित हो वह भ्रष्टाचार के विरूद्ध कैसे कदम उठा सकती है? सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने का नाटक होता रहा। छोटी मछलियों को पकड़कर सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकती रही। परंतु इससे जन मुहिम पर फर्क नहीं पड़ा। बाबा रामदेव को आमलोगों का समर्थन मिलते देख सत्ता प्रतिष्ठान में हड़कंप मच गया। जे.पी. आंदोलन की पुनरावृत्ति से भयग्रस्त सरकार ने 2 जून को सत्याग्रह के लिए दिल्ली आ रहे बाबा की अगुवानी के लिए प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में चार मंत्रियों का दल हवाई अड्डे पर भेजा। परंतु यह सब आंदोलन को कमजोर करने की व्यूह रचना थी। इसका प्रयोग मनमोहन सरकार अन्ना हजारे के साथ कर चुकी थी। परंतु बाबा के साथ दाल नहीं गली। उधर कांग्रेस के मुखपत्र 'संदेश' ने इस सरकारी पहल को अनुचित बताया और इसकी आलोचना की। अगले दिन दिल्ली में बाबा रामदेव के साथ कपिल सिब्बल और सुबोधकांत सहाय की बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने कहा कि 99 प्रतिशत मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही बाबा की मांगों को लेकर सरकार समिति का गठन करेगी।

कालेधन की कालिख

Global financial integrity की रिपोर्ट के अनुसार

- नौ साल में 47 सौ 25 अरब कालेधन की अवैध निकासी देश के बाहर।
- साल 2000 से 2008 के बीच करीब 104 अरब डॉलर यानी 47 सौ 25 अरब बाहर गया है। जो 2010–11 की शिक्षा बजट की तुलना में करीब दस गुणा है।
- 9 साल में अवैद्य धन निकासी के मामले में भारत का एशिया में पांचवां स्थान है।

According to data provided by the Swiss Bank India has more black money than rest of the world combined!

- India topping the list almost $ 1500 billion black money in Swiss Bank.
- The total black money accounts for 40% of GDP of India.

According to another report of GFI on illicit financial flows (illegal capital flight)

- From 1948 through 2008 India lost of total of $ 213 billion.
- The present value of India's total IFFs is at least $ 462 billion.
- Total Capital flight represents approximately 16.6 percent of India's GDP as of year-end 2008; (51)

Official website of Global Financial Intergrity

India : Composition of Underground Economy 50% of GDP (as of 2008, US Dollars)

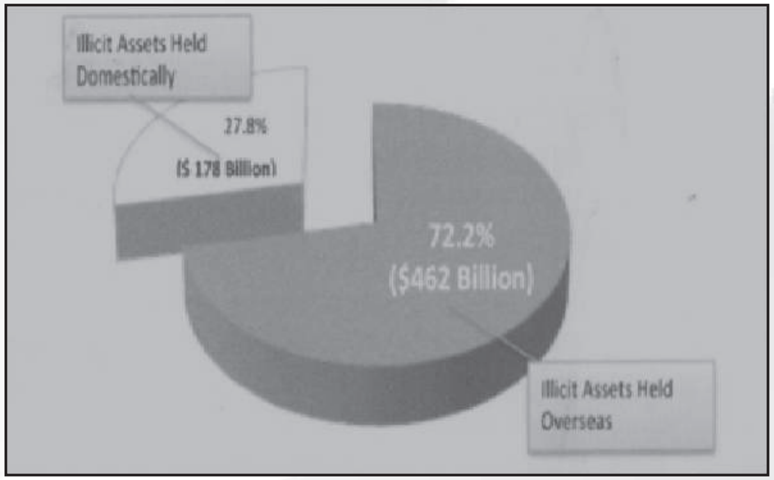

Financial Flows from India: "1948-2008" Table 8, pp67)
Clearly, the fact of corruption is undeniable

Cumulative Illicit Finacial Flows and Percent of GDP : 1948-2008

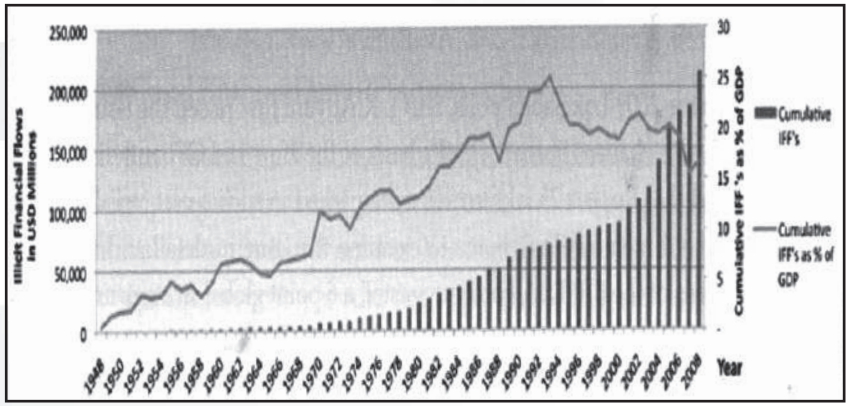

- Illicit financial flows out of India grew at a rate of 11.5 percent per year while in real terms they grew by 6.4 percent per year; (51)
- India lost $ 16 billion per year from 2002-2006. (1)

भारत के बैंकों में भी है जमा लावारिस धन

कुल बिना दावे की राशि	:	13 अरब, 60 करोड़, 31 लाख, 59 हजार, 646.89 रुपये
भारत स्थित विदेशी बैंकों में	:	47,31,67,698 रुपये
देश के दूसरे निजी बैंकों मे	:	15,03,23,106 रुपये

बाकी के पब्लिक सेक्टर के बैंकों में

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	:	10,47,223 खातों में 88,15,84,887 रुपये
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	:	75,261 खातों में 14,43,61,403 रुपये
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	:	86,311 खातों में 8,59,66,644 रुपये
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	:	40,114 खातों में 8,85,83,351 रुपये
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	:	1,22,628, खातों में 30,03,40,111 रुपये
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	:	532 खातों में 35,13,378 रुपये
एचडीएफसी बैंक	:	2500 खातों में 1,89,94,831 रुपये
आईसीआईसीआई बैंक	:	90,094 खातों में 28,19,25,887 रुपये

यह स्थिति 31 दिसंबर, 2009 की है और इस धन पर 10 सालों से किसी ने दावा नहीं किया है।

स्त्रोतः वर्ष 2011 के शुरु में आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल की अर्जी का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया जवाब

सत्याग्रहियों की मांगें

1. अध्यादेश के जरिए कालेधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए।
2. करोड़पति भ्रष्टाचार के मगरमच्छों को मृत्युदंड या उम्रकैद
3. एक साल में सुनवाई पुरी करने का कानून
4. भारतीयों के विदेशी खातों का खुलासा
5. यूएसए कनवेंशन पर हस्ताक्षर
6. पांच सौ व एक हजार नोटों को बंद करना
7. लोकपाल विधेयक को पारित कराना
8. भूमि अधिग्रहण के अधिनियम 1948 को रद्द किया जाए।
9. जेनेटेक्ली मोडिफाइड खाद्य पदार्थों पर रोक।
10. शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा व मातृभाषा हो।
11. चुनाव के लिए सरकारी फंड एवं अनिवार्य मतदान

इन मांगों में विदेशी बैंकों में जमा कालेधन को भारत में लाने के लिए राजनीतिक, वैधानिक और राजनयिक प्रक्रिया शुरु करने की मांग सबसे अहम है।

भ्रम, दुष्प्रचार, चरित्र हनन के हथकंडे

प्रेस वार्ता में सुबोधकान्त सहाय और कपिल सिब्बल

4 जून की सुबह तक रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरूद्ध सत्याग्रहियों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी और सत्याग्रह शुरु हो गया। सायं पांच बजे तक साफ हो गया कि सरकार के तमाम आश्वासन टालमटोल करने की एक चाल थी। फिर सरकार एवं सत्तारूढ़ पार्टी ने 'नरम' रूख त्याग कर आक्रामक रूख अख्तियार किया। बाबा रामदेव की मांगों के बजाय उनके व्यक्तित्व पर ओछे दर्जे की बहस करने लगी। ऐसा ओछापन जे.पी. आंदोलन के दौरान भी देखा गया था। कालेधन का मुद्दा सरकार के लिए बिजली करंट जैसा हो गया। सरकार आंदोलन का 'दमन करो या मरो' के सिद्धांत पर अपने बचाव में लग गई। आरोप–प्रत्यारोप के बीच सत्याग्रह का पहला दिन संयमित भाषण के साथ गुजरा। किसी को तनिक भी आशंका नहीं थी और न ही किसी ने संभावना व्यक्त की कि सरकार बर्बरतापूर्वक तरीके उसी रात सत्याग्रह को कुचलेगी।

कानून और व्यवस्था के लिए बनी पुलिस बल का दुरूपयोग

रामलीला मैदान के बाहर पुलिस की तैयारी

रामलीला मैदान में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित पुलिस बल तैनात था। लोगों ने इस तैनाती को महज कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा के दृष्टि से देखा था। पुलिस एवं जांच एजेंसियां लोकतांत्रिक देश में आम लोगों के प्रति प्रतिबद्ध होती हैं। औपनिवेशिक शासन या अधिनायकवादी सरकार इन एजेंसियों को अपने राजनीतिक हितों के लिए दुरूपयोग करती हैं। अतः प्रश्न उठता है: जांच एजेंसियों और पुलिस बल की प्रतिबद्धता सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति हो या भारत के संविधान के प्रति?

रामलीला मैदान में मध्य रात्रि में अभियान चलाने का फैसला राजनैतिक था। यह बात रविवार को दिल्ली पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने कही। गौरतलब है कि रामलीला मैदान में ही बाबा रामदेव आमरण अनशन पर बैठे थे। यह अभियान तड़के एक बजे के बाद शुरू हुआ और कुछ घंटों के भीतर ही खत्म हो गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह राजनैतिक फैसला था। अन्यथा हम अभियान नहीं चलाते*।

हिन्दुस्तान, 5 जून 2011

राष्ट्रभक्ति गीतों की धुन पर झूमते सत्याग्रही

* 5 जून की सुबह दस बजे दिल्ली पुलिस का बयान

फासीवादी हमला

दूर दराज से आए हजारों अनशनकारी रात को रामलीला मैदान के पंडाल में सो गए। मध्यरात्रि के पश्चात जब पूरा देश निश्चिंतता से सो रहा था, दमनकारी सरकार जाग रही थी। राक्षसीवृत्ति का ऐसा प्रदर्शन स्वतंत्र भारत में कभी भी नहीं देखा गया। पुलिस राजनीतिक निर्णय के आधार पर वह सब कर रही थी, जो किसी भी लोकतांत्रिक एवं सभ्य समाज के लिए कलंक है।

दमन से अनजान रात्रि विश्राम करते सत्याग्रही   फोटोः प्रेट्र

रात के अंधेरे में जब रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर रहे योग गुरु बाबा रामदेव के समर्थन में 50 हजार से अधिक लोग भूखे सो रहे थे तो दिल्ली पुलिस के हजारों जवानों ने उनपर हमला बोल दिया, आंसू गैस के गोले दागे गए, मंच तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, सो रहे लोगों को घसीटा गया, महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया, बच्चों तक को नहीं बक्शा गया। देश के कोने–कोने से आए लोगों पर ढाए गए बर्बर जुल्म ने अपातकाल की याद ताजा कर दी।

पंजाब केसरी, 6 जून, 2011, विशेष संपादकीय, अश्विनी कुमार

सत्ता का षड्यंत्र

सत्याग्रहियों को चेतावनी नहीं दी गई। उन्हें पंडाल छोड़ने का अवसर नहीं दिया गया। सीधे लाठी गोली की भाषा में बात की गई।

पुलिस ने जो हड़कंप मचाया उससे भगदड़ मच सकती थी और उस भगदड़ में कितनी जाने जाती इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। परंतु सत्याग्रहियों के संयम एवं अनुशासन ने इस घटना को रोक लिया।

...और इस तरह पुलिस ने मंच पर धावा बोल दिया

फोटोः नई दुनिया, राजन चंदेल/हरीश कुमार

पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से अमानवीय और क्रूर है। इससे साफ पता लगता है कि सरकार को अहिंसक आंदोलन की समझ ही नहीं है और वह भ्रष्टाचार के प्रति भी गंभीर नहीं है।

मेधा पाटेकर, सामाजिक कार्यकता

बर्बरता का प्रदर्शन

कोई सरकार अपने कर्मों से किस तरह खुद को कलंकित कर सकती है, इसका निकृष्ट उदाहरण है केंद्रीय सत्ता। चार जून की रात केंद्रीय सत्ता की नाक के नीचे रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के समर्थकों को यहां तक कि महिलाओं, बच्चों और बुजूर्गों के साथ जो हुआ उसे बर्बरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार ने निहत्थे लोगों के साथ पशुवत व्यवहार कर खुद को शर्मसार करने के साथ ही देश को यह अवसर दिया है कि वह उसकी निंदा और भर्त्सना करने के लिए आगे आए। रामलीला मैदान में सोते हुए लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई अपातकाल की याद दिलाने के साथ ही ढुलमूल और दिन–प्रतिदिन आम जनता का विश्वास खोती जा रही मनमोहन सिंह सरकार के अहंकार को भी रेखांकित करती है। दैनिक जागरण, 6 जून, 2011

चार घंटे तक पुलिसिया आतंक चलता रहा। लोग सदमें में थे। पुलिस की डंडे से सत्याग्रहियों की नींद खुली। आंसू गैस के गोले दागे गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि देश के संसद के नाक के नीचे यह सब क्यों हो रहा है। पुलिस के निशाने पर एक–एक सत्याग्रही था। सरकार का यह सीधा आदेश था कि इन्हें मारो भगाओ। पुलिस बेफिक्र काम कर रही थी। स्वतंत्र भारत की सरकार का औपनिवेशिक शासन जैसा व्यवहार था।

साभार : PTI

यह नागरिक के मूलभूत अधिकार और मानवाधिकारों का हनन है। इमरजेंसी की कड़वी यादें एक बार फिर ताजा हो गई। सोते हुए लोगों पर लाठी बरसाना बर्बरता है।

पूर्व न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े

कुशासन का कलंक

जालियावाला बाग का दृश्य

एक लाख मासूम लोगों को रामलीला मैदान में आधी रात को लाठियों और आंसू गैस छोड़कर भगाने की बर्बर कार्रवाई मनमोहन सिंह सरकार द्वारा की गई। ये लोग दिनभर अनशन पर थे। कड़ी सूरक्षा व्यवस्था के कारण इस भीड़ में कोई व्यक्ति हथियार या लाठी तक नहीं ले जा सकता था। हजारों निहत्थों असहाय लोगों पर ऐसे पुलिस कार्रवाई आधुनिक भारत के 64 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुई और कभी होनी भी नहीं चाहिए। **आलोक मेहता, विशेष संपादकीय, नई दुनिया, 6 जून, 2011**

1919 में जनरल डायर ने इसी प्रकार रौलेट एक्ट का विरोध करने आए लोगों पर गोलियां दागी थी। शांतिपूर्ण विरोध प्रकट करने का अधिकार औपनिवेशिक या अधिनायकवादी सरकार ही छीनती है। तब काले कानून का विरोध करने लोग एकत्र हुए थे अब कालेधन के विरूद्ध लोग एकत्र हुए थे।

रामलीला मैदान का दृश्य

बाबा रामदेव के अभियान के खिलाफ हुई कार्रवाई 'नग्न फांसीवाद'। बाबा रामदेव को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि महिलाओं और बच्चों को पीटा गया। यह मुझे जलियावाला बाग कांड की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष को रामदेव और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उप प्रधानमंत्री

विनाश काले विपरीत बुद्धि

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को आधी रात के बाद जैसा सुलूक किया वह बर्बर तो है ही, उससे तानाशाही की बू भी आती है। दूर–दराज से आए लोगों महिलाओं और बच्चों पर लाठियां चलाने वाली सरकार ने बाद में जहां अपनी अमानवीयता को जायज ठहराया, वहीं दिल्ली पुलिस ने तर्क गढ़ा कि बाबा की जान को खतरा था। भ्रष्टाचार खुलासे नहीं बल्कि उसके खिलाफ उठी आवाज सरकार को परेशान करती है।

अमर उजाला

रामलीला मैदान में महिला समर्थकों ने दिखाए उत्पीड़न के निशान

साभार : नई दुनिया

पुलिस आतंक का शिकार दूध पीने वाले मासूम बच्चे, उम्रदराज बुजुर्ग और महिलाएं भी हुई। संभवतः लोकतंत्र में आस्था ने उन्हें निर्भीक बनाकर खींच लाया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोंचा था कि उन्हीं के वोटों से चुनी सरकार डाकुओं की तरह रात के अंधेरे में कायरता का मिशाल पेश करेगी।

रामलीला मैदान में पुलिस कार्रवाई के बाद अपने परिवार से बिछड़ने के बाद रोती-बिलखती महिला। ● सोनू मेहता

वर्तमान स्थिति के लिए सरकार अकेली जिम्मेदार है। चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो या फिर रामदेव का अनशन, सरकार ने लोकतंत्र की ताकत को कम करके आंका है।

– डी राजा, भाकपा के राष्ट्रीय सचिव

गोबेल्स का दुष्प्रचार

यह बेहद अफसोस की बात है कि कांग्रेस के नेता और मंत्री इस कार्रवाई को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का वे कितना सम्मान करते हैं। लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद कांग्रेस बाबा रामदेव को ठग बताने में जुट गई। यह समझ से परे है कि ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार ने पहले पलक पांवड़े क्यों बिछाए और उनके भ्रष्टाचार और काला धन जैसे अत्यंत अहम मुद्दों पर बातचीत क्यों करती रही?

जनसत्ता, 8 जून, 2011, संपादकीय

वृद्धों को भी नहीं छोड़ा गया... साभार : AFP

निहत्थे असहाय लोगों पर पुलिस डंडे बरसा रही थी। बुजूर्ग बच्चे और महिलाओं को अपवाद नहीं माना। निर्दयता का नग्न नाच केंद्रीय मंत्रिमंडल देख रहा था। वे एक दूसरे को शाबाशी दे रहे होंगे।

जर्मनी के नाजी पार्टी के पास एक गोबेल्स था जो मानता था कि एक झूठ को सौ बार बोलने से सच हो जाता है। इस सरकार और कांग्रेस के पास गोबेल्स के शिष्यों की कमी नहीं हैं।

रामलीला मैदान में बाबा के समर्थकों पर की गई कार्रवाई के बाद ऐसा लगता है कि सरकार मानसिक संतुलन खो बैठी है और इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो लोग उन्हें ठग बता रहे हैं वेह पहले अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस से बड़ा ठग कोई नहीं है।

मुलायम सिंह यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी

साभार : हिन्दुस्तान

सत्ता की निर्ममता

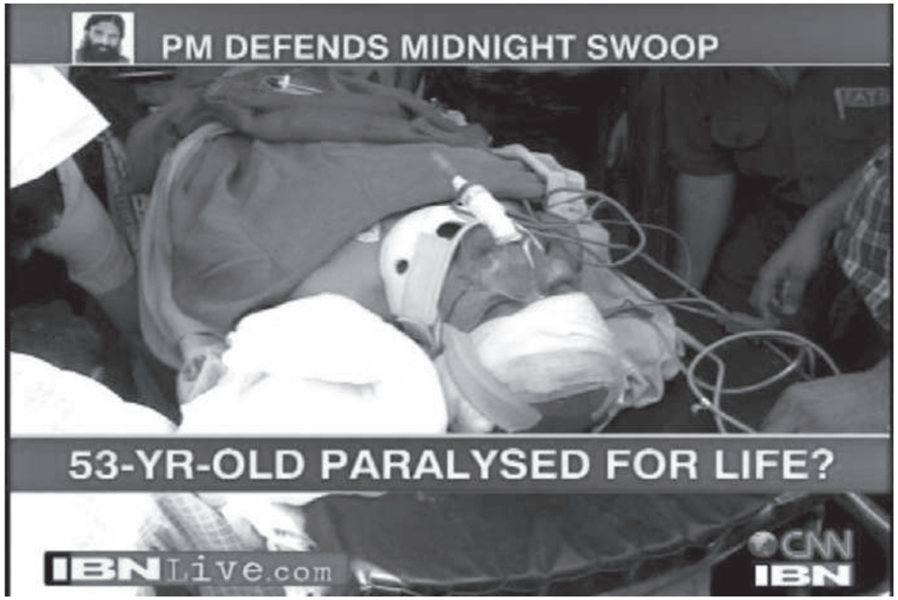

पुलिसिया निर्दयता की शिकार राजबाला

इस निर्दयता ने हरियाणा से आई 51 वर्षीय श्रीमती राजबाला को इतना आघात किया कि वह मौत से जूझ रही है। क्या कोई सभ्य समाज इस जुर्म को भूल सकता है?राजबाला के इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सत्याग्रह करना उसका आपराधिक जुर्म

था?कौन देगा इसका उत्तर? जे.पी. आंदोलन के दौरान इसी तरह आंदोलनकारियों को बेरहमी से पीटा जाता था। आंदोलनकारियों का नारा था – "चाहे जैसा हमला होगा–हाथ हमारा नहीं उठेगा।" इसी अहिंसक प्रतिरोध से पशुवत सरकार घबराती है। इसी ने साम्राज्यवाद को भारत से बाहर फेंका था। राजबाला भी इसी अहिंसक प्रतिरोध में जख्मी है। यह सत्याग्रह के प्रति आस्था की मिशाल है।

हमारा आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विशेष संज्ञान ले और निर्देश दे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग घटनाक्रम की स्वतंत्र एवं अलग से जांच करें। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

मायावती, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

आपातकाल की काली याद

शनिवार रात को मौजूदा सरकार ने जो कुछ किया वह लोकतंत्र की हत्या है। हर दूसरे दिन कोई जिम्मेदार मंत्री या अधिकारी किसी न किसी घोटाले में फंस रहे हैं लेकिन दोषियों को सजा देने के बजाय उसपर लीपापोती की नापाक कोशिश हो रही है। सरकार ने तानाशाही रवैया अपना लिया है और देश को 'बनाना रिपब्लिक' बनाना चाहती है।

शांति भूषण, अमर उजाला, 6 जून, 2011

देश में आज सैंकडों ऐसें लोग राजनीति, मीडिया एवं सार्वजनिक जीवन में हैं जिन्होंने आपातकाल में सरकार का प्रतिरोध किया था, जुल्म सहा था, वे सभी सरकारी की कार्रवाई से हतप्रभ थे। यह आत्मलोचन का समय है कि एक कमजोर एवं भ्रष्ट सरकार इतनी अधिनायकवादी तरीके से कैसे दमनकारी हो गई?

सरकार अपना संतुलन खो चुकी है। केंद्र ने बाबा से बातचीत के लिए चार मंत्रियों को भेजा, लेकिन दूसरी तरफ पांच हजार पुलिसकर्मियों को भेजकर निर्दोष लोगों को मारा–पीटा गया।

सुषमा स्वराज, नेता प्रतिपक्ष

षडयंत्र

The midnight police swoop on yoga exponent and telestar 'Baba' Ramdev and his supporters was arbitrary, brutal, and anti-democratic. A peaceful assembly had suddenly been set upon and tens of innocent people injured for no fault of their own.

The Hindu, June 6. 2011

74 में छात्र आंदोलन शुरु हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व था। सरकारी दमन छात्रों और नौजवानों पर हुआ। 4 नवंबर 1974 को जे.पी. पर सुनियोजित पुलिसिया हमला हुआ। जे.पी. को मारने का यह सुनियोजित षड्यंत्र था। अगर जनसंघ के नेता स्वर्गीय नानाजी देशमुख तब नही होते तो जे.पी. पर यह हमला प्राणघाती सिद्ध होता। नानाजी ने स्वयं को आगे कर जे. पी. की जान को बचा लिया।

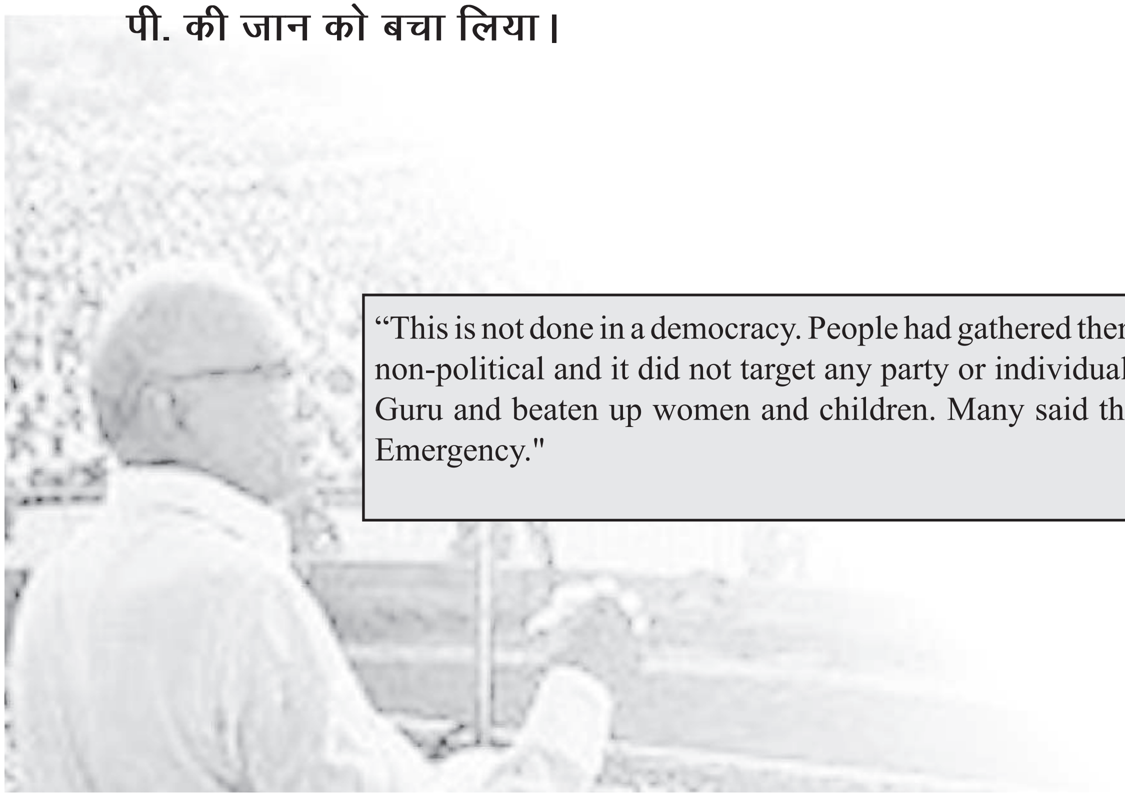

"This is not done in a democracy. People had gathered there on their own to support a social cause. The agitation was non-political and it did not target any party or individuals. The government should not have humiliated the yoga Guru and beaten up women and children. Many said the incident was reminiscent of Jallianwala Bagh and the Emergency."

Dr. Mohan Bhagwat, Sarsnanghachalak, RSS

संतों, सन्यासियों का प्रगतिशील कदम

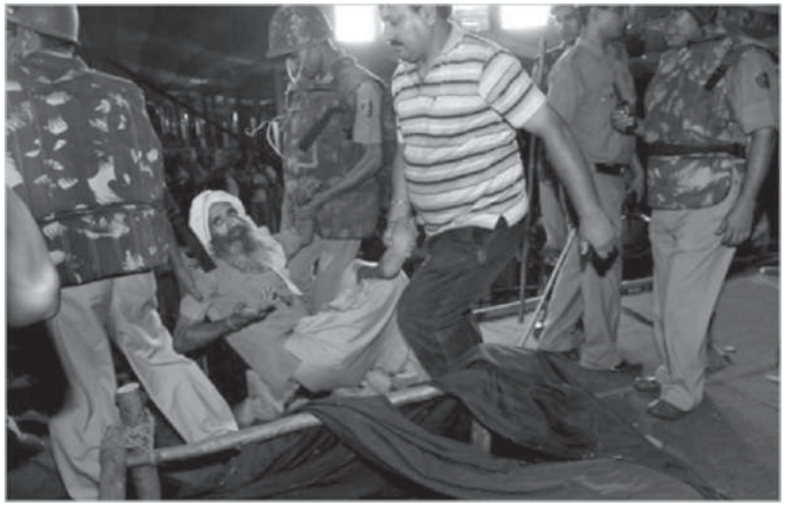

साभार : नई दुनिया

साधु सन्यासियों के मन में भी अनचाही राजनीति के प्रति आक्रोश है। संतों एवं सन्यासियों का समाजिक–राजनीतिक सुधार हेतु प्रगतिशील उपयोग का समकालीन भारत में एक उदाहरण है। वे सत्ता में न भागीदारी मांग रहे थे, न व्यवस्था उलटने की बात कर रहे थे और न ही किसी विद्रोह का नेतृत्व। सिर्फ एक कानून की मांग कर रहे थे : कालेधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए। वे जनचेतना के सार्थक माध्यम बन रहे हैं। साधु–सन्यासियों का अपना एक गैर राजनीतिक दायरा है परंतु देश–समाज के राजनीतिक जीवन में अनेक अवसर आते हैं जब संतों–सन्यासियों का प्रगतिशील उपयोग सामाजिक–आर्थिक संरचना बदलने में होता है। लैटिन अमेरिका में न्यू पीपुल्स चर्च ने ऐसी ही जन–जागृति की थी।

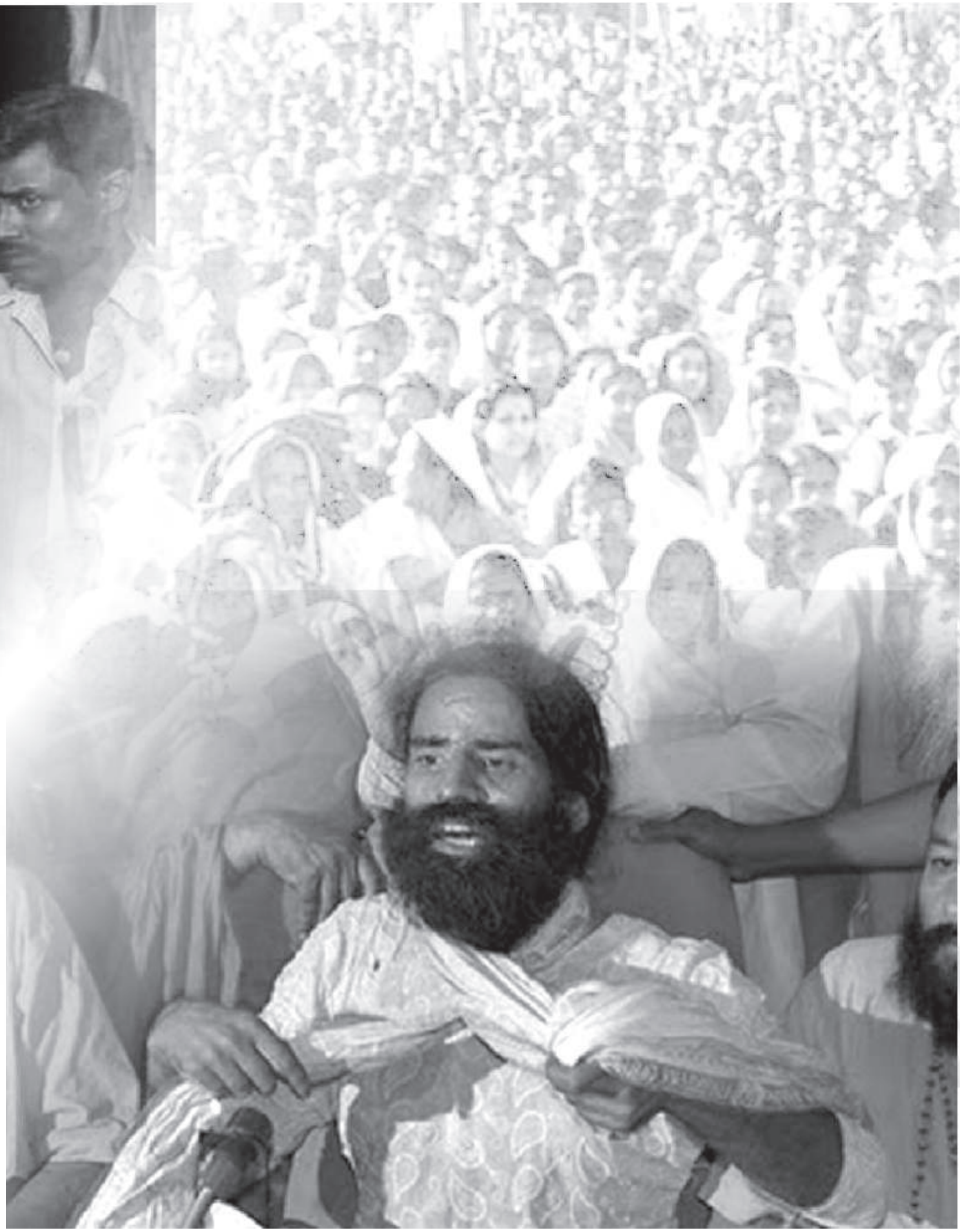

कांग्रेस ने जो काम 4 नवंबर 1974 को जे.पी. के साथ किया उसी की पुनरावृति 4 जून 2011 को की गई। बाबा रामदेव की खोज ऐसे की जा रही थी जैसे 26/11 का आतंकवादी कसाब उस भीड़ में छिपा हुआ हो। सत्याग्रही महिलाओं ने चतुरता से बाबा रामदेव की जान की रक्षा की। बाबा को छद्‌मवेश में पुलिस बर्बरता से बचाया गया।

> मेरे ऊपर भी हमले की कोशिश की गई और यह मुझे मरवाने की साजिश थी।
>
> —स्वामी रामदेव

निर्दोष, अहिंसक एवं आध्यात्मिक वृत्ति के साधु सन्यासियों को भी नहीं छोड़ा गया। भारतीय परंपरा का इतना बड़ा उपहास खोजने पर भी इतिहास में नहीं मिलता है। उन्हें बर्बर तरीके से पीटा गया। यह एक असाधारण घटना है। बाबा रामदेव सिर्फ सत्याग्रही ही नहीं थे वे भारतीय संस्कृति योग एवं आयुर्वेद को लेकर यूरोप में लोकप्रिय हो रहे थे। अतः उनकी हैसियत को कम करने एवं उन्हें अपमानित करने से किसको शांति मिली? 'कौन रोम के नीरो' की तरह बंद किले में ठंढ़ी सांस ले रहा था?यह सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, सांकेतिक रूप से साधु परंपरा का उपहास भी था। किसे इसमें हर्षोल्लास हो रहा था?

कार्रवाई के दौरान घायल सत्याग्रही

दया की भीख मांगते बुजुर्ग

अस्पताल में सत्याग्रही

बीती रात रामदेव के शांतिपूर्ण धरणा पर की गई कार्रवाई चौंकाने वाली और कठोर थी। केंद्र सरकार ने अलोकतांत्रिक व्यवहार किया।

—नवीन पटनायक, सीएम उडीसा

भारत में सत्याग्रह और अनशन का इतिहास पुराना है। साम्राज्यवाद को महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह एवं उपवासों से हिलाकर रख दिया था। जे.पी. आंदोलन ने इंदिरा गांधी के अधिनायकवाद को खुली चुनौती दी थी। आपातकाल के दमन भी लोगों को नहीं तोड़ पाई। हजारों लोग जेल गए। इनमें स्कूली बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी थीं। अनेक प्रकार की यातनाएं दी गईं। परंतु भूमिगत आंदोलन से सरकार त्रस्त थी। जॉर्ज फर्नांडीस, नानाजी देशमुख, सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे लोग पूरे सरकारी प्रतिष्ठान के लिए सरदर्द बने रहे।

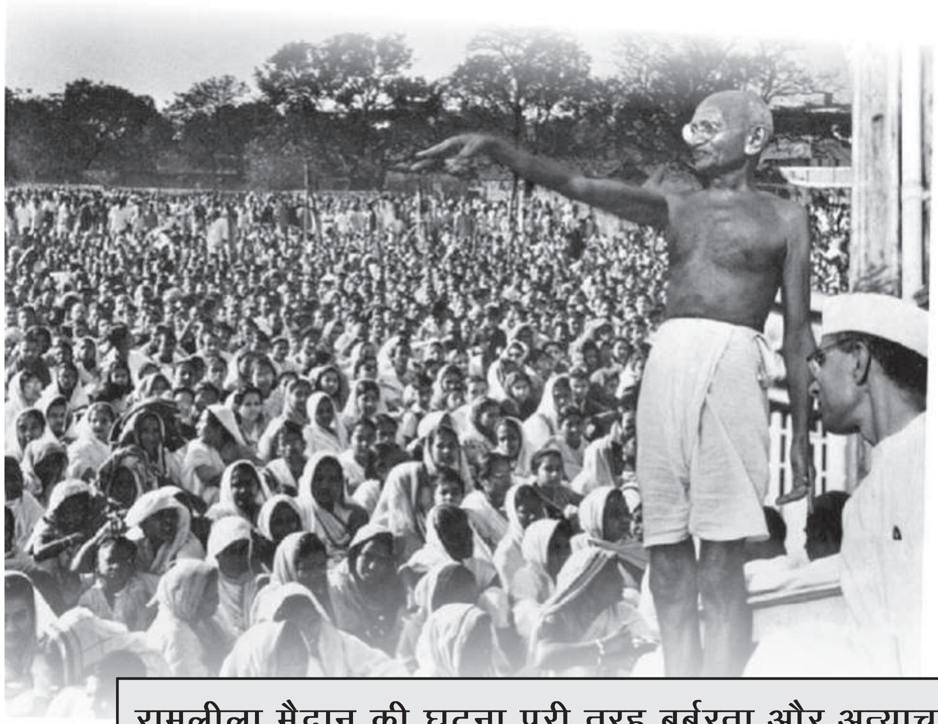

आपातकाल के शिकार जॉर्ज फर्नांडीस

रामलीला मैदान की घटना पूरी तरह बर्बरता और अत्याचार है। स्वामी रामदेव जी अनशन पर बैठे थे और उन्हें तथा अनशनकारियों को आधी रात जिस प्रकार से हटाया गया, वह लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के समान है। आज 5 जून है और आज ही के दिन जयप्रकाश नारायण ने 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। लगता है सरकार के मन में फिर से लोकतंत्र को कुचलने की इच्छा पैदा हो गई है।

नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की साहस की दाद देनी चाहिए। वे फक्र से कहते हैं कि इस दमन और बर्बरता का विकल्प नहीं था। क्या वे सत्याग्रही संसद पर हमला करने वाले थे? क्या राजबाला हथियारबंद होकर भारतीय जनतंत्र को कैद करने के लिए प्रतिबद्ध थी?

रामलीला में रावणलीला के बाद

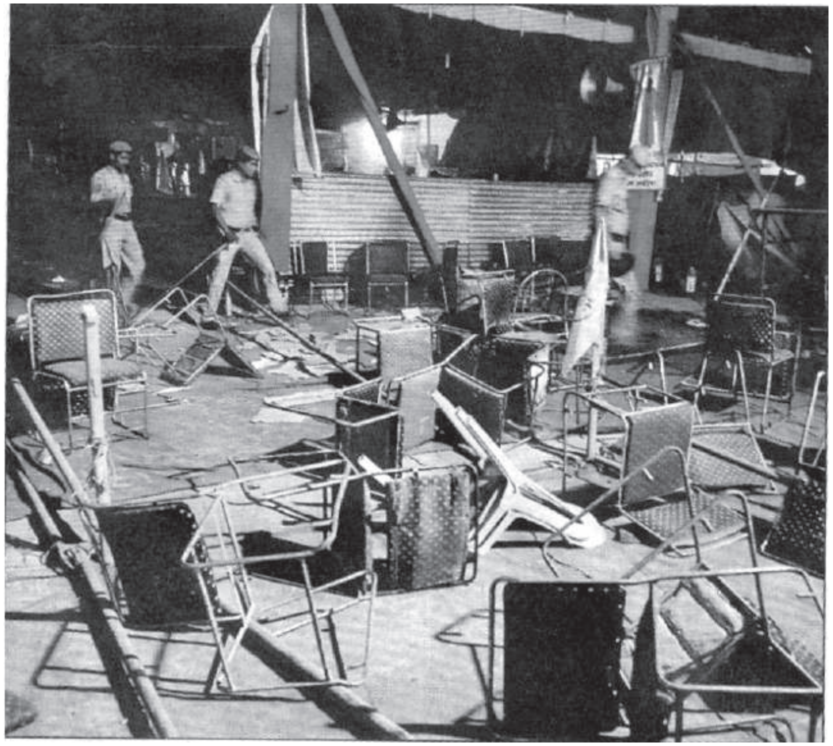

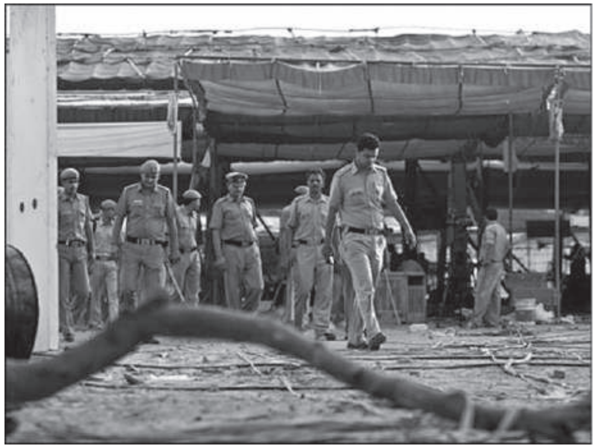

...कुछ सुबूत तो नहीं छूटे!

> यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और अनैतिक कार्रवाई है। इसके लिए सरकार को तत्काल देशवासियों से माफी मांगना चाहिए। साफ है कि जो लोग देशहित की बात कर रहे हैं, सरकार उन्हें दबा रही है।
>
> – चंद्रबाबू नायडू, प्रमुख तेलगु देशम पार्टी

कांग्रेस के नेता एवं सरकार के मंत्री बदजुबानी से लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है कि सरकार एवं पार्टी और गठबंधन की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी कहती हैं कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं थी। राजबाला की कराह क्या उन तक नहीं पहुंची? जो व्यवस्था परिवारवाद में सिमट गई हो वह निरंकुश एवं संवेदनहीन हो जाती है। क्या दमन के चक्रव्यूह में नागरिक समाज स्वच्छंद होकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अहसास कर सकता है?कोई विचारशील व्यक्ति या थींक टैंक नीति निर्माण की पहल आत्मविश्वास के साथ कर सकता है? जनतंत्र सिर्फ संरचना में नहीं व्यवहार में भी होता है। क्या हम जनतंत्र के सोपान में आगे बढ़े हैं या नीचे गिरे हैं? क्या काले धन पर आपत्ति और सत्याग्रह आपराधिक कार्य है? इन प्रश्नों का उत्तर हर भारतीय को ढुंढना पड़ेगा।

'Black Money' front under control...request permission to march towards 'Jan Lokpal'

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध।

—राष्ट्रकवि दिनकर

जर्मनी में नाजियों के अत्याचार के प्रति लोगों की अवचेतना एवं आलस्य को अभिव्यक्त करती ये पंक्तियां

First they came for the **Jews,**
and I didn't speak out because
I wasn't a Jew.

Then they came for the **trade unionists,**
and I didn't speak out because
I wasn't a trade unionist.

Then they came for the **communists,**
and I didn't speak out because
I wasn't a communist.

Then they came for me
and there was no one left to speak out for me.

(Pastor **Martin Niemölle**)

दैनिक भास्कर
योग गुरु के सत्याग्रह को कुचलने पर केंद्र की किरकिरी, अनशन अब हरिद्वार में
बाबा पर बर्बरता से बवंडर
ugee at midnight
attered hopes & broken limbs
DNA Correspondent
NEW DELHI
At least a hundred men and women who had come to attend Baba Ramdev's camp
Kumar, has fractured his skull, reportedly from a lobbed shell. Sharda Gupta, who had come from Meerut, said, "Male cops physically pushed us on the ground without even look-
m of Pyramid
F BRANDS ▸▸ 4
बचा केवल बिखरा सामान उजड़ा मैदान
Govt's Brute Power Yoga Makes for a Bad Postur
पुलिस ने मंच को भी आग के हवाले किया!
लिस की लाठी नहीं तोड़ पाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जुनून
पुलिसिया कार्रवाई में
आधा दर्जन से ज्यादा
दखा हाल
क यह हुआ रामलीला मैदान में
Ramlila raids leave 71 injured
सुबह दिखे पुलिसिया बर्बरता के
नई दिल्ली। बाबा रामदेव के सत्याग्रह को तहस-नहस करने के लिए पुलिस ने हर तरह के हथकंडे अपनाए। अनशनकारियों का कहना है कि पुलिस ने न सिर्फ लोगों को मारपीट कर पंडाल से खदेड़ दिया बल्कि मंच को भी आग के हवाले कर दिया। अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि जो लोग पत्थर मार रहे थे वे भी पुलिस
कहना है कि पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले से मंच पर आग लगी।
अफरातफरी मच गई और कुछ लोग जख्मी भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस आरोप का निराधार बताया है।
और योग करने वाले ये लोग कैसे पत्थर लेकर वहां पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों का